

कैबिनेट से दिलाई जाएगी मंजूरी, 23 हजार से ज्यादा को रोजगार मिलने की उम्मीद

पांच मेगा प्रोजेक्ट को सरकार 254 करोड़ रुपए की मदद देगी

हिन्दुस्तान

खास

राज्य मुख्यालय | अजित खरे

आने वाले वक्त में यूपी में पांच नए उद्योग अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। प्रदेश सरकार इसके साथ ही इन्हें 254 करोड़ रुपये का इन्सेंटिव देने को तैयार हो गई। कैबिनेट की बैठक में जल्द इससे संबंधित प्रस्ताव मंजूर होगा। पश्चिमी यूपी में लगे इन फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन, स्मार्ट फ़ोन, टच पैनल, एलईडी आदि इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों का निर्माण करेंगे। इसके जरिए 23 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

इन परियोजनाओं को इन्सेंटिव देने की तैयारी

* निवेश (करोड़ रुपये में)

निवेशक	निवेश	रोजगार	उत्पाद	जिला गौतमबुद्धनगर
सत्कृति इन्फोटेनेमेंट फंडा आडियो इंडिया	205	3500	वॉशिंग मशीन, एलईडी, टीवी	डीएमआईसी, ग्रेटरनोएडा
लियनचुआग इलेक्ट्रानिक्स	281	3300	टच पैनल, लिक्विड क्रिस्टल	नोएडा
केएचवाई इलेक्ट्रानिक इंडिया	358.15	10150	एन्ड्रायड स्मार्ट फोन	नोएडा
वीवो मोबाइल इंडिया	439	5300	स्मार्टफोन, काम्पोनेंट्स	यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण
केएच वेटेक इंडिया	266	1500	इलेक्ट्रानिक्स उपकरण	ग्रेटर नोएडा

शासन की हाईपावर इम्पावर्ड कमेटी ने पांच निवेशकों सत्कृति इन्फोटेनेमेंट फंडा आडियो इंडिया, लियनचुआग इलेक्ट्रानिक्स, केएचवाई इलेक्ट्रानिक इंडिया, वीवो मोबाइल इंडिया, केएच वेटेक इंडिया द्वारा निवेश करने के एवज में मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है। इन वित्तीय प्रोत्साहन में कैपिटल सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी, इंटरेस्ट सब्सिडी, एसजीएसटी

प्रतिपूर्ति, जमीन पर छूट शामिल है। यह सारे प्रोत्साहन 253.56 करोड़ रुपये के हैं।

सरकार इन्हें इन पांच कंपनियों को यह प्रोत्साहन 8 साल में देगी। पहले साल यानी 2020-21 में 174.4 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अगले वित्तीय वर्ष में 54.35 करोड़ दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 व वित्तीय वर्ष 2024-25 में 23.6-23.6 करोड़

रुपये दिए जाएंगे। बाकी की रकम इसके बाद के सालों में दी जाएगी। इनमें कुछ कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है या करने की ओर अग्रसर हैं। बताते चलें कि 200 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट लगाने पर मिलने वाले इन्सेंटिव की मंजूरी कैबिनेट से लेनी होती है। इन वित्तीय प्रोत्साहन में कैपिटल सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क में छूट, ब्याज उपादान प्रमुख हैं।